ब्रहस्पतिवार, 4 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

अफगानिस्तान सीरीज से पहले रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर नजर

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

मनोज बाजपेयी का भावुक खुलासा, बोले– सफलता मिली, लेकिन बहुत कुछ खो दिया

Page-05

दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी स्थित एक गेस्ट हाउस में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में भवन में क्षमता से अधिक कमरे संचालित किए जाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के संकेत मिले हैं। इस हादसे ने राजधानी में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गेस्ट हाउस में 21 की मौत

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी इलाके में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने राजधानी की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 'फ्लोरिश स्टे' नामक गेस्ट हाउस में लगी आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने इसे महज दुर्घटना नहीं बल्कि गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला बना दिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित परिसर को दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) योजना के तहत केवल छह कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी। लेकिन जांच में सामने आया कि परिसर में करीब 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इनमें बेसमेंट में बनाए गए कमरे भी शामिल थे, जो सुरक्षा मानकों के विपरीत बताए जा रहे हैं। हादसे के समय गेस्ट हाउस में लगभग 40 लोग ठहरे हुए थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आग लगने के दौरान अधिकांश लोग सो रहे थे, जिससे उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इमारत में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही रास्ता था। आपातकालीन निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी।दमकल विभाग और पुलिस की टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गेस्ट हाउस के पास वैध फायर एनओसी थी या नहीं। यदि बिना सुरक्षा मंजूरी के इतने बड़े स्तर पर संचालन किया जा रहा था तो संबंधित अधिकारियों और संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस हादसे ने एक बार फिर राजधानी में भवन सुरक्षा नियमों के पालन पर बहस छेड़ दी है।

बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूद गई मां

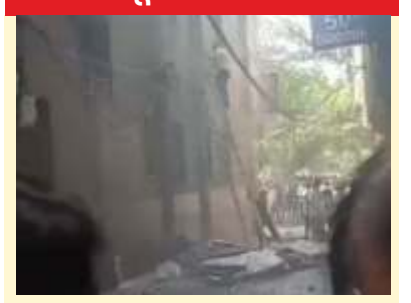

होटल का मुख्य दरवाजा बंद होने के कारण लोग नीचे नहीं आ पा रहे थे और आग की लपटें तेजी से कमरों की तरफ बढ़ रही थीं। तीसरी मंजिल पर फंसी एक महिला जब धुएं के कारण पूरी तरह बेबस हो गई, तो उसने अपने मासूम बच्चे को बचाने के लिए एक आत्मघाती लेकिन मजबूर कदम उठाया। महिला ने अपने कलेजे के टुकड़े को कसकर अपने सीने से लगाया और सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। आपको बता दें कि आनन-फानन में तीसरी मंजिल से नीचे गिरने के कारण महिला और उसके बच्चे को बेहद गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत यह रही कि नीचे खड़े स्थानीय लोगों ने वहां कुछ हद तक सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ था, जिससे दोनों की जान तो बच गई, लेकिन ऊंचाई से गिरने के प्रभाव के कारण वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के तुरंत बाद दोनों को लहूलुहान हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हादसे के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बताया कि होटल के झरोखों और खिड़कियों से लोग मदद के लिए चीख रहे थे। महिला का अपने बच्चे के साथ तीसरी मंजिल से कूदने का यह विजुअल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन प्रवक्ताओं के नामों का किया एलान

कॉकरोच जनता पार्टी ने जनता और मीडिया से बात करने के लिए तीन प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। सीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट कॉकरोच इज बैक के जरिए सोशल मीडिया पर इन नियुक्तियों की जानकारी दी। पोस्ट के अनुसार, खोजी पत्रकार सौरव दास को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इनके अलावा, राजनीतिक शोधकर्ता, लेखिका और फिल्म निर्माता विजेता दहिया तथा आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और वैश्विक प्रबंधन परामर्श कंपनी मैकिंजी से जुड़े रहे आशुतोष रांका को भी पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। सीजेपी ने कहा है कि वह भारत में राजनीतिक विमर्श को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पहल का नेतृत्व नई पीढ़ी के नेता करेंगे। पोस्ट में दावा किया गया है कि पार्टी का उद्देश्य देश में नई राजनीतिक सोच और संवाद को बढ़ावा देना है, जिसके लिए युवा नेतृत्व को आगे लाया जा रहा है। सौरव दास को कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने का अनुभव है। सीजेपी ने दावा किया है कि साल 2025 में इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें सौरव दास की प्रमुख भूमिका थी। वहीं विजेता दहिया यूट्यूब पर कई शोध और कंटेंट क्रिएशन कर चुकी हैं। विजेता दहिया ने किताबें भी लिखी हैं।

यूपी में छह माह तक हड़ताल पर रोक, ESMA लागू

उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक जनसेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह निर्णय आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) 1966 के तहत लिया है। अधिसूचना जारी होने के बाद अस्पताल, बिजली, जलापूर्ति, सफाई और परिवहन जैसी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।सरकार के अनुसार हाल के दिनों में विभिन्न विभागों में धरना-प्रदर्शन और हड़ताल की गतिविधियों के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। इससे आम जनता को बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आगामी त्योहारों और संभावित बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।नई अधिसूचना के तहत केवल औपचारिक हड़ताल ही नहीं, बल्कि सामूहिक अवकाश, कार्य बहिष्कार और सेवा बाधित करने वाली गतिविधियों को भी हड़ताल की श्रेणी में माना जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित सर्वोपरि है और आवश्यक सेवाओं को किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने दिया जाएगा।ESMA के उल्लंघन पर छह महीने तक की जेल, आर्थिक दंड या दोनों का प्रावधान है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ संगठनों ने इसे कर्मचारियों के अधिकारों पर अंकुश बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह जनहित में लिया गया है।

बंगाल में टीएमसी पर संकट के बादल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। पार्टी से निष्कासित दो विधायकों द्वारा खुद को 'असली टीएमसी' बताने और 50 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। घटनाक्रम ने पार्टी नेतृत्व के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।सूत्रों के अनुसार, निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई प्रशासनिक बैठक में टीएमसी के कई विधायक शामिल हुए, जिससे राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला है।इस बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाते हुए टीएमसी की सभी संगठनात्मक समितियों और सहयोगी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि संगठन की व्यापक समीक्षा की जाएगी और उसके बाद नए सिरे से संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें ममता बनर्जी के अगले कदम और पार्टी के पुनर्गठन पर टिकी हुई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली नेता रबी लामिछाने से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने से मुलाकात कर दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति का महत्वपूर्ण साझेदार है और नई राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों देशों के सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने रबी लामिछाने की साझा विकास और समृद्धि की भावना का स्वागत किया।इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेपाली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन और आपसी विश्वास बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा हुई। अमित शाह ने नेपाल की नई सरकार को शुभकामनाएं देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की।रबी लामिछाने ने अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की। वार्ता में विकास साझेदारी, कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने माना कि भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध दोनों देशों की साझेदारी की मजबूत नींव हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में नए राजनीतिक नेतृत्व के उदय के बीच यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे विकास, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

भारत-वेनिजुएला के बीच ऊर्जा सहयोग पर होगी बड़ी वार्ता

कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत पहुंचीं

वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अनिश्चितता के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में जुटा है।इसी क्रम में वेनिजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पांच दिवसीय भारत दौरे पर पहुंची हैं। इस यात्रा को ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहयोग के नए अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत और वेनिजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से वेनिजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज बुधवार को पांच दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचीं। ऐसे समय में यह यात्रा हो रही है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण अस्थिरता का सामना कर रहा है। ऊर्जा आयात पर काफी हद तक निर्भर भारत वैकल्पिक स्रोतों और नए साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके कारण इस दौरे को विशेष महत्व दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपने प्रवास के दौरान डेल्सी रोड्रिगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा ऊर्जा और वाणिज्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच कच्चे तेल की आपूर्ति, पेट्रोकेमिकल्स, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा व्यापारिक संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए नई संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के महीनों में भारत द्वारा वेनिजुएला से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि के बाद यह यात्रा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और वह ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। वेनिजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है, इसलिए दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का दायरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

वेनिजुएला की सरकार भी भारत को एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदार के रूप में देखती है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में वर्षों से सहयोग रहा है, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों ने इस संबंध को और अधिक रणनीतिक महत्व प्रदान किया है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि इस यात्रा के दौरान ऊर्जा आपूर्ति, निवेश या व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण समझौता होता है, तो उसका असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर भी दिखाई दे सकता है।

राजनयिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह दौरा केवल तेल और ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा। भारत और वेनिजुएला तकनीक, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश, डिजिटल सहयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी नई साझेदारियों की संभावनाएं तलाश सकते हैं। ऐसे में डेल्सी रोड्रिगेज की यह यात्रा भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच बढ़ते संबंधों का एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ताओं और संभावित समझौतों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी रहेगी।

ब्रिटेन की विदेश मंत्री का एशिया दौरा, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

ब्रिटेन की विदेश मंत्री इवेट कूपर इन दिनों एशिया दौरे पर हैं, जहां उनका मुख्य उद्देश्य चीन और भारत के साथ वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करना है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया कई भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। चीन में अपनी यात्रा के दौरान कूपर ने वहां के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक व्यापार, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उनका भारत आने का कार्यक्रम है, जहां वे विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। ब्रिटेन और भारत के बीच हाल के वर्षों में व्यापारिक तथा रणनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देश रक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में 'यूके-इंडिया विजन 2035' को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटेन अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए एशिया के प्रमुख देशों के साथ संबंधों को नई दिशा देना चाहता है। चीन और भारत दोनों विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे में लंदन इनके साथ संवाद बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस यात्रा के परिणाम आने वाले वर्षों में ब्रिटेन की एशिया नीति को प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के दौर में यह दौरा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

TMC में बड़ी टूट! अलग गुट बनाने का दावा करेंगे पेश

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ममता की पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। ममता की पार्टी में टूट का खतरा बढ़ गया है। बंगाल विधानसभा में TMC के बागी विधायकों ने बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बागियों ने 58 विधायकों के साइन वाला लेटर स्पीकर को सौंप दिया है और ऋतब्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की है। सियुली साहा और जावेद खान को विपक्ष का उप नेता बनाने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में आज बड़ी टूट की आशंका है। टीएमसी के दो बागी विधायक रीताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने खुद को असली टीएमसी विधायक घोषित करते हुए दावा किया है कि उनके पास 58 विधायकों के साइन हैं। ऋतब्रत को ममता बनर्जी ने अभी हाल में ही पार्टी से निकाला है। बागी विधायक मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने कहा कि उन्होंने भी पत्र पर साइन किए हैं। हमें सही आंकड़ा नहीं पता। मैं बाहर से सुन रहा हूं कि कई विधायकों के हस्ताक्षर मिले हैं। मैं बस यही सुन रहा हूं। वहीं एक अन्य बागी विधायक प्रिया पॉल ने कहा कि "मैं अंदर (विधानसभा) जा रही हूँ, मीटिंग के बाद बताऊँगी।" टीएमसी को भी पार्टी में टूट के खतरे का अहसास है। इसलिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विधानसा स्पीकर को खत लिखकर शोभनदेव चट्टोपध्याय को नेता विपक्ष का मान्यता देने की मांग की है। इसके साथ ही टीएमसी ने विपक्ष के उप नेता के लिए आशिमा पात्रा, नयना बंदोपाध्याय और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक बनाने की मांग की है। अपने खत में कल्याण बनर्जी ने पिछली परंपराओं का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने स्पीकर का ध्यान इस तरफ दिलाया है कि जब वो 15 मई को विधानसभा स्पीकर चुने गए थे तो शोभनदेव नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें आसन तक ले गए थे। इसके बाद स्पीकर ने अपने भाषण में नेता विपक्ष के रूप में शोभनदेव का जिक्र किया है।

म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा संपन्न, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की भारत यात्रा बुधवार को संपन्न हो गई। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्राओं में से एक रही, जिसे दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों की सीमा भी साझा है, जिसके कारण सुरक्षा, व्यापार और संपर्क परियोजनाओं पर सहयोग का विशेष महत्व है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ह्लाइंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ भारतीय नेताओं से मुलाकात की।बैठकों में सीमा सुरक्षा, संपर्क परियोजनाओं, क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत लंबे समय से म्यांमार में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सहयोग करता रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए म्यांमार सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क बढ़ाने की भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में म्यांमार की भूमिका केंद्रीय मानी जाती है। वहीं म्यांमार भी आर्थिक और विकासात्मक सहयोग के लिए भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है।राजनयिक विश्लेषकों का कहना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा और क्षेत्रीय स्थिरता को भी मजबूती मिलेगी। ऐसे समय में जब एशिया में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, भारत और म्यांमार के बीच सहयोग का विस्तार दोनों देशों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।

अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ा खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों से बढ़ी चिंता

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की खबरों के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है, जबकि ऊर्जा बाजार में भी अस्थिरता देखी जा रही है।रिपोर्टों के अनुसार, कुवैत और बहरीन में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कुवैत ने अपने वायु रक्षा तंत्र को सक्रिय करते हुए संभावित खतरों को रोकने की कार्रवाई की, जबकि बहरीन प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह जारी की।अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक वार्ताओं में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे तनाव कम करने के प्रयासों के पक्षधर हैं, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात दोहराई है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व का है। खाड़ी क्षेत्र से होकर दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस व्यापार संचालित होता है। यदि तनाव और बढ़ता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए निकट भविष्य में स्थिति सामान्य होती नहीं दिखाई दे रही है। दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि इनके निर्णयों का प्रभाव वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।

संपादक की कलम से

पानी जीवन का आधार है। मानव जीवन, कृषि, उद्योग और पर्यावरण सभी की निर्भरता जल पर है। इसके बावजूद आज दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, भूजल के अत्यधिक दोहन और जल स्रोतों के प्रदूषण ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। ऐसे समय में जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता बन चुका है। भारत में अधिकांश क्षेत्रों की जल आवश्यकताएं मानसून पर निर्भर हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं सूखे जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इससे जल संसाधनों का संतुलन बिगड़ रहा है। कई शहरों और गांवों में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट आम बात हो गई है। यह संकेत है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में समस्या और गंभीर हो सकती है।जल संरक्षण की शुरुआत व्यक्तिगत स्तर से की जा सकती है। घरों में पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन को अपनाना और जल के प्रति जिम्मेदार व्यवहार विकसित करना आवश्यक है। छोटी-छोटी बचत भी बड़े परिणाम दे सकती है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग जल की खपत को काफी हद तक कम कर सकता है।सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जलाशयों, तालाबों और नदियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियां लागू करनी होंगी। शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था विकसित करना भी समय की मांग है। जल संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। पानी की कमी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, उद्योगों की गति को धीमा करती है और लोगों के जीवन स्तर पर सीधा असर डालती है। इसलिए जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है।आज यदि हम पानी बचाने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे। जल की हर बूंद अनमोल है और उसका संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का सबसे प्रभावी मार्ग है।

डी.के. शिवकुमार ने संभाली सत्ता की कमान

कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन को बताया नई शुरुआत

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की लंबे समय से चल रही अटकलों पर बुधवार को विराम लग गया।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।इस बदलाव को कांग्रेस आगामी राजनीतिक चुनौतियों और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देख रही है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कर्नाटक की राजनीति में बुधवार को एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष D. K. Shivakumar ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राजधानी Bengaluru में आयोजित भव्य समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर के रूप में देखा गया, जिसने राज्य में सत्ता और संगठन के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में नया संदेश देने का प्रयास किया।पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर लगातार बैठकों और मंथन का दौर चल रहा था। कांग्रेस नेतृत्व राज्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए नेतृत्व परिवर्तन के विकल्प पर विचार कर रहा था। अंततः कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से डी.के. शिवकुमार के नाम पर सहमति बनी। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा प्रस्तुत किया और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी में विशेष तैयारियां की गई थीं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे तथा वीवीआईपी आवागमन को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए। राज्य सरकार ने कुछ प्रशासनिक कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश भी घोषित किया था ताकि समारोह के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में शिवकुमार ने राज्य के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुशासन और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक में हुआ यह नेतृत्व परिवर्तन केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी पड़ सकता है। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति के तहत कांग्रेस इस बदलाव को महत्वपूर्ण मान रही है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया बताते हुए नई सरकार के कामकाज और उसके प्रदर्शन पर नजर रखने की बात कही है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि नया नेतृत्व राज्य की राजनीतिक और विकास संबंधी चुनौतियों का सामना किस प्रकार करता है।

महाराष्ट्र के नागपुर विधान परिषद उपचुनाव बना भाजपा-कांग्रेस की प्रतिष्ठा का प्रश्न

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के नागपुर विधान परिषद उपचुनाव ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की इस सीट पर होने वाला चुनाव भले ही सीमित मतदाताओं के बीच हो, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ व्यापक माने जा रहे हैं।यह सीट राज्य के राजस्व मंत्री के विधानसभा राजनीति में सक्रिय होने के बाद रिक्त हुई थी। भाजपा ने प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. राजीव पोतदार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने मुखर प्रवक्ता अतुल लोंढे को मैदान में उतारा है। दोनों दलों ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है और स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।भाजपा का दावा है कि उसे सहयोगी दलों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त है और वह आराम से जीत दर्ज करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि स्थानीय स्तर पर असंतोष और विकास से जुड़े मुद्दों के कारण मुकाबला अपेक्षा से अधिक कड़ा होगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि मतदाता केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे।राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार नागपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में यदि कांग्रेस यहां बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसे विपक्षी राजनीति के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। वहीं भाजपा इस सीट को अपने प्रभाव क्षेत्र की परीक्षा के रूप में देख रही है। इसलिए दोनों दलों के वरिष्ठ नेता लगातार चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।उपचुनाव के नतीजे भले ही राज्य सरकार की स्थिरता को प्रभावित न करें, लेकिन इससे आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक संदेश अवश्य जाएगा। यही कारण है कि एक सीट का यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में विशेष महत्व प्राप्त कर चुका है।

शिक्षा मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने

कांग्रेस ने बढ़ाया दबाव

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

शिक्षा व्यवस्था और हाल के परीक्षा विवादों को लेकर केंद्र सरकार तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांग रहे हैं तथा परीक्षा प्रबंधन में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं।कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि हाल के महीनों में विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने छात्रों और अभिभावकों का विश्वास कमजोर किया है। पार्टी ने शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।वहीं केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि जहां भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिली है, वहां जांच और सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप भी लगाया है।इस बीच संसद और राजनीतिक मंचों पर शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े विषय प्रमुख चर्चा का केंद्र बन गए हैं। विभिन्न छात्र संगठनों ने भी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, तकनीकी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की है। कई स्थानों पर छात्रों और युवा संगठनों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए हैं, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है।विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे युवा देश में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखते हैं। आने वाले समय में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम और विपक्ष की रणनीति इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख एजेंडे में बनाए रख सकती है। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर जारी बहस ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है।

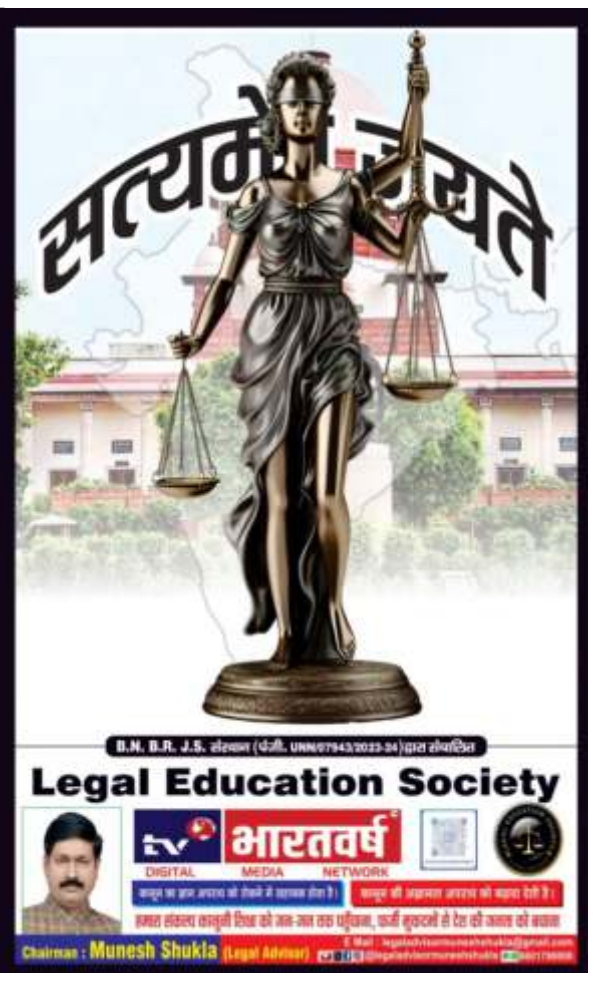

सीयूईटी-यूजी परीक्षा दोबारा कराने का फैसला

परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर उठे सवाल

देश की उच्च शिक्षा प्रवेश प्रणाली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तकनीकी गड़बड़ियों से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए सीयूईटी-यूजी 2026 परीक्षा को पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। इस फैसले ने देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, तकनीकी क्षमता और छात्रों के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है।सीयूईटी-यूजी देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का प्रमुख माध्यम बन चुका है। हर वर्ष लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा के दौरान आई तकनीकी समस्याओं ने छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एनटीए ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए नए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं और कहा है कि सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराना एजेंसी की प्राथमिकता है।पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। कभी पेपर लीक के आरोप लगे तो कभी तकनीकी खामियों ने परीक्षार्थियों को परेशान किया। हाल ही में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को लेकर भी देशभर में विवाद देखने को मिला था, जिसके बाद परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे।शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल परीक्षा प्रणाली आधुनिक और सुविधाजनक अवश्य है, लेकिन इसके लिए मजबूत तकनीकी ढांचा और प्रभावी निगरानी तंत्र आवश्यक है। यदि परीक्षा के दौरान सर्वर, नेटवर्क या सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसका सीधा प्रभाव छात्रों के प्रदर्शन और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। कई छात्रों ने शिकायत की है कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उनका समय नष्ट हुआ और वे अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सके।शिक्षाविदों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली केवल प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा आयोजित करने तक सीमित नहीं है। इसमें साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, मूल्यांकन प्रणाली और शिकायत निवारण तंत्र भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि इन क्षेत्रों में कमजोरी रहती है तो पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। यही कारण है कि अब विशेषज्ञ राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट और सुरक्षा मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं।इस बीच छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बार-बार होने वाले बदलावों से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित होती है। कई विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश समय-सारिणी में संशोधन करना पड़ता है, जिससे शैक्षणिक कैलेंडर पर भी असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए तो छात्रों का विश्वास दोबारा मजबूत किया जा सकता है।सरकार और परीक्षा एजेंसियों के सामने अब चुनौती केवल परीक्षा आयोजित करने की नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों को यह भरोसा दिलाने की भी है कि उनकी मेहनत और भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। आने वाले दिनों में सीयूईटी-यूजी की पुनर्परीक्षा और उसके परिणाम इस दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देंगे।

भारत में इस माह शुरू होगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स

भारत की आर्थिक और सांख्यिकीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार इस महीने से देश में पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की नई श्रृंखला भी जारी की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई के आकलन को अधिक सटीक और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से उत्पादों के मूल्य में होने वाले बदलावों का आकलन किया जाता है। हालांकि डब्ल्यूपीआई मुख्य रूप से वस्तुओं पर आधारित है और इसमें सेवा क्षेत्र शामिल नहीं होता। नई पीपीआई प्रणाली में वस्तुओं के साथ-साथ बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, रेलवे और अन्य सेवा क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। इससे उत्पादकों के स्तर पर बढ़ती लागत और मूल्य परिवर्तन की अधिक व्यापक तस्वीर सामने आएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। सरकार का उद्देश्य निवेशकों, उद्योगों और नीति निर्माताओं को अधिक विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक नीतियां बेहतर ढंग से बनाई जा सकें।उद्योग संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि उत्पादन लागत में होने वाले बदलावों का सटीक आकलन होने से कंपनियां मूल्य निर्धारण और निवेश संबंधी निर्णय अधिक प्रभावी तरीके से ले सकेंगी। वहीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे महंगाई के रुझानों को शुरुआती स्तर पर पहचानने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत को एक मजबूत और आधुनिक सांख्यिकीय प्रणाली की आवश्यकता थी। ऐसे में पीपीआई का शुभारंभ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत- न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज का ऐलान

32 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में वितरित हुई खेल सामग्री

देश में खेल संस्कृति को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विभिन्न राज्यों के 32 हजार से अधिक सरकारी विद्यालयों में खेल सामग्री वितरित की गई है। इस कदम का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है।विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई खेल सामग्री में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम जैसे लोकप्रिय खेलों के उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स, योग और शारीरिक फिटनेस से जुड़े विभिन्न संसाधन भी स्कूलों को प्रदान किए गए हैं। इससे छात्रों को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और विद्यालयों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी।शिक्षा और खेल विशेषज्ञों का मानना है कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। साथ ही नियमित खेल गतिविधियां विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करती हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के अनेक विद्यालयों में खेल संसाधनों की कमी के कारण प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। नई खेल सामग्री उपलब्ध होने से ऐसे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा और वे जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे।

अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतिस्पर्धाओं पर भारतीय खिलाड़ियों की नजर

जून महीने की शुरुआत के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन कैलेंडर का व्यस्त दौर शुरू हो गया है। दुनिया के प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में शामिल इंडोनेशिया ओपन 2026 में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। खेल विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रतियोगिता आगामी वैश्विक आयोजनों की तैयारी और खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म को परखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।पिछले एक दशक में भारतीय बैडमिंटन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय खिलाड़ियों ने कई बड़े टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित किया है। इसी कारण अब विश्व मंच पर भारतीय शटलरों से बेहतर प्रदर्शन और पदक जीतने की उम्मीदें लगातार बढ़ी हैं। इंडोनेशिया ओपन जैसे उच्च स्तरीय टूर्नामेंट खिलाड़ियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनकी तकनीकी और मानसिक तैयारी का भी आकलन होता है।कोचों और विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे टूर्नामेंटों में हासिल परिणाम खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग को सीधे प्रभावित करते हैं। बेहतर प्रदर्शन से रैंकिंग में सुधार होता है, जिससे भविष्य की प्रतियोगिताओं में बेहतर ड्रॉ और अवसर प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि भारतीय खिलाड़ी लंबे समय से इस प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं और अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें भी इस प्रतियोगिता पर टिकी हुई हैं। प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारतीय शटलर अपनी प्रतिभा और अनुभव के दम पर शानदार प्रदर्शन करेंगे तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करेंगे। यदि खिलाड़ी अपनी लय बरकरार रखने में सफल रहते हैं, तो यह आगामी बड़े टूर्नामेंटों के लिए भी सकारात्मक संकेत साबित हो सकता है।

अफगानिस्तान सीरीज से पहले रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर नजर

भारतीय क्रिकेट टीम आगामी अफगानिस्तान श्रृंखला की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। इस बीच टीम के दो प्रमुख और अनुभवी खिलाड़ियों रोहित शर्मा तथा हार्दिक पांड्या की फिटनेस चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दोनों खिलाड़ियों को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों और फिटनेस प्रशिक्षकों की निगरानी में उनकी शारीरिक स्थिति का अंतिम मूल्यांकन किया जा रहा है।भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना प्रस्तावित है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी। इस श्रृंखला को भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में कई बड़ी प्रतियोगिताएं और चुनौतीपूर्ण दौरे निर्धारित हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन और चयनकर्ता किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस को लेकर कोई जोखिम लेने के पक्ष में नहीं हैं।रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या लंबे समय से भारतीय टीम के अहम स्तंभ रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों का अनुभव और नेतृत्व क्षमता टीम को मजबूती प्रदान करती है। चयन समिति का मानना है कि यदि दोनों खिलाड़ी पूरी तरह फिट होकर टीम में शामिल होते हैं तो इससे युवा खिलाड़ियों को भी मार्गदर्शन मिलेगा और टीम का संतुलन मजबूत होगा।सूत्रों के अनुसार, मेडिकल टीम दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यदि रिपोर्ट संतोषजनक रहती है तो दोनों खिलाड़ियों को श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं किसी भी प्रकार की शारीरिक असुविधा पाए जाने पर चयनकर्ता सावधानी बरतते हुए उन्हें अतिरिक्त आराम देने का विकल्प भी चुन सकते हैं।क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों की निगाहें अब बीसीसीआई की अंतिम घोषणा पर टिकी हुई हैं। प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करें और अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी श्रृंखला में भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करें।

वायरल वीडियो देख लोग बोले- नमूनों की कमी नहीं!

मजे से भूसा खा रहा शख्स

इंटरनेट पर वायरल होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं. इसी कड़ी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है. जिसे देख कोई भी हैरान रह जाए. एक वायरल वीडियो में युवक मजे से भूसा खाता नजर आ रहा है.

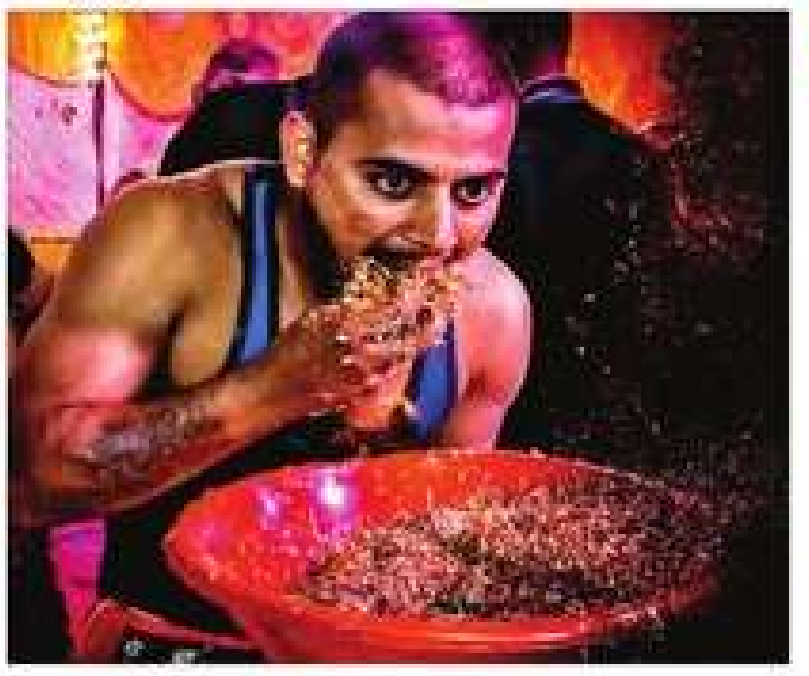

अब तक सिर्फ गाय- भैंस, बकरी व अन्य मवेशियों को ही भूसा खाते देखा होगा. किसी इंसान को भूसा खाते शायद ही कभी किसी ने देखा हो. इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने के दौर में लोगों का यह भ्रम भी टूट जाएगा. क्योंकि, इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक मजे से भूसा खाते दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rudhrayadav001 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है - अभी तक तो मुझे लगता था कि भूसा सिर्फ जानवर ही खाते हैं, लेकिन आज देख लिया कि इंसान भी भूसा खा सकते हैं. देखिए कैसे यह लड़का बड़े मजे से भूसा को दबा-दबा कर, चबा-चबाकर खा रहा है. ऐसा नजारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने हाथ में एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा भूसा लेकर उसे चाव से खा रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी समारोह में अपने इस करतब का प्रदर्शन कर रहा है.

ठूंस- ठूंसकर खाया भूसा

एक मिनट के इस वीडियो में शख्स ने एक नहीं, बल्कि कई बार भूसा खाया. वह मुंह में ठूंस- ठूंसकर भूसा भरता है, फिर उसे मजे से चबा-चबाकर खाता दिखाई दे रहा है. आसपास खड़े लोग भौचक होकर उसे ही एकटक देखे जा रहे हैं. इस वीडियो पर लोगों ने काफी मजे लिए हैं.

भारत और अमेरिका के वर्क कल्चर में क्या है फर्क?

सोशल मीडिया पर अक्सर अमेरिका की वर्क लाइफ और वहां की संस्कृति को लेकर पोस्ट वायरल होती रहती हैं. ऐसी ही एक पोस्ट इन दिनों चर्चा में है. अमेरिका में रह रहे भारतीय युवक रवि आर. कुमार ने एक पोस्ट साझा करते हुए वहां के कामकाज के तरीके के बारे में बताया. उन्होंने लिखा कि अमेरिका में कई दफ्तर सुबह 6:30 बजे ही काम शुरू कर देते हैं. ऐसे में दोपहर 3 बजे तक लोगों का दिन का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है.

शादी की शर्त ने मचाया बवाल

अपर कास्ट या फिर 80 लाख की कमाई जरूरी

क्या आज भी शादी में प्यार से ज्यादा जाति और पैसा मायने रखते हैं? हाल ही में सामने आई एक घटना ने इसी सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है. एक पढ़ी-लिखी और सफल महिला ने अपनी शादी के लिए ऐसी शर्त रख दी, जिसने आधुनिक सोच पर सवाल खड़े कर दिए- या तो दूल्हा 'उच्च जाति' का हो, वरना उसकी कमाई 80 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए. इस एक शर्त ने दिखा दिया कि आज भी समाज में जाति और स्टेटस की सोच कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, भले ही हम खुद को कितना भी प्रगतिशील क्यों न मान लें.

कहानी एक 32 साल की महिला की है, जो अपना खुद का फैशन

बिजनेस चलाती है. वह एक अच्छे और पढ़े-लिखे परिवार से आती है. उसके पिता आईपीएस अधिकारी हैं और मां एक टीचर हैं. यानी बाहर से देखने पर वह एक आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाले परिवार की लगती है. लेकिन जब बात शादी की आई, तो उसने दूल्हे के लिए एक खास शर्त रखी.

3 लाख महीना भी पड़ रहा कम

कपल ने महंगाई के डर से चुना 'नो किड्स' फॉर्मूला

आज के समय में बढ़ती महंगाई और ऊंचे खर्चों ने लोगों की जिंदगी के बड़े फैसलों को भी बदल दिया है. जहां पहले शादी के बाद बच्चा होना एक सामान्य बात मानी जाती थी, वहीं अब कई कपल इस पर दोबारा सोच रहे हैं.

गुरुग्राम के एक कपल ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया है, अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद उन्होंने बच्चा न करने का निर्णय लिया, और इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. गुरुग्राम में रहने वाले एक दंपति ने बच्चा न करने का फैसला लिया है, और इसकी वजह है बढ़ती महंगाई और खर्चे. इस दंपति की सालाना कमाई करीब 36 लाख रुपये है, जो सुनने में काफी अच्छी लगती है. पति हर महीने लगभग 2 लाख

रुपये कमाते हैं और पत्नी 1 लाख रुपये कमाती हैं. लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि वे अभी बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते.

इस बात को उनके रिश्तेदार हर्ष गुप्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया. उन्होंने बताया कि कागजों पर तो यह दंपति आर्थिक रूप से मजबूत लगता है, लेकिन असल जिंदगी में खर्च इतने ज्यादा हैं कि वे परिवार बढ़ाने से बच रहे हैं. कपल का कहना है कि गुरुग्राम जैसे शहर में एक अच्छा घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि वे एक ठीक-ठाक 1BHK फ्लैट भी नहीं खरीद पा रहे हैं. ऐसे में उनका सवाल है कि जब वे खुद के लिए सही जगह नहीं ले पा रहे, तो बच्चे के लिए बेहतर माहौल कैसे देंगे. इसके अलावा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बहुत ज्यादा है.

प्राइवेट स्कूलों की फीस हर महीने करीब 35,000 से 40,000 रुपये तक हो सकती है, जो उनके लिए उनके लिए संभालना मुश्किल है. यही कारण है कि उन्होंने अभी बच्चा न करने का फैसला लिया है. आजकल ऐसे कई शहरी कपल हैं, जो डबल इनकम, नो किड्स यानी DINK लाइफस्टाइल अपना रहे हैं.

मनोज बाजपेयी का भावुक खुलासा, बोले– सफलता मिली, लेकिन बहुत कुछ खो दिया

बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और संजीदा अभिनेताओं में शुमार मनोज बाजपेयी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी बेमिसाल अदाकारी के दम पर सिनेमा जगत में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, जहां पहुंचने का सपना हर उभरता हुआ कलाकार देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले और कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके मनोज बाजपेयी अब अंदर से जीवन की मोह-माया से ऊपर उठ चुके हैं? हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया के मशहूर पॉडकास्ट शो में पहुंचे मनोज बाजपेयी ने अपनी निजी जिंदगी, करियर और सफलता के पीछे छिपे दुखों को लेकर कई ऐसे हैरान करने वाले खुलासे किए हैं, जिसने उनके फैंस को बेहद भावुक कर दिया है। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में अपने दिल की बात शेयर की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह अब एक्टिंग को किसी मजबूरी की तरह नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, "मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊं, तो पिछले 10 साल से मेरे मन में बीच-बीच में यह ख्याल आता है कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ कर बैठ जाऊं। लेकिन तभी अचानक कोई ऐसा बेहतरीन किरदार मेरे सामने आ जाता है, जिसे निभाने का लालच मैं छोड़ नहीं पाता और फिर कैमरे के सामने आ जाता हूं। मैं सिर्फ घर चलाने या पैसे कमाने के लिए एक्टिंग नहीं करना चाहता।" इसी बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी एक दबी हुई इच्छा भी जाहिर की। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं आपके

च
लिए
दौरान
की।
शो में पहली

सा
जो
पाता।"

बार यह स्वीकार कर रहा हूं कि आजकल मेरा मन बिल्कुल मसालेदार कमर्शियल फिल्में करने का हो रहा है। मेरा मन है कि मैं ऐसी 'नॉनसेंस' कॉमेडी फिल्में करूं, जिनमें गानों पर नाचूं और सुबह घर से बिना किसी तैयारी या कैरेक्टर रिसर्च के निकलूं और शाम को बिना कुछ सोचे काम खत्म करके वापस आ जाऊं।" मनोज बाजपेयी ने बेहद भावुक अंदाज में स्वीकार किया कि आज वह जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज यानी अपने माता-पिता का साथ कुर्बान किया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, "जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो पाता हूं कि इस दौलत-शोहरत को कमाने के फेर में मैंने बहुत कुछ खो दिया। मैं अपने पेरेंट्स के साथ कभी वक्त ही नहीं बिता पाया। शुरुआत में मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा, फिर एक्टर बनने का सपना लेकर दिल्ली आ गया, जहां अंग्रेजी सीखने और रोटी का जुगाड़ करने में ही वक्त निकल गया। उस दौर में मां-बाप से सिर्फ कभी-कभार चिट्ठियों के जरिए ही बात हो पाती थी।" उन्होंने आगे कहा, "जब सब कुछ हासिल हो जाता है, तब समझ आता है कि क्या इन भौतिक चीजों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना वाकई सही था? जब मेरे माता-पिता गुजरे, तब हम बस एक-दूसरे को ठीक से समझने की शुरुआत ही कर रहे थे। काश! मुझे अपने पिता के थ थोड़ा और वक्त मिल जाता और मां के साथ कुछ मनमुटाव थे, उन्हें मैं बैठकर सुलझा

पंचायत चुनाव टालने पर कोर्ट की नाराजगी

सरकार और आयोग से मांगा जवाब

विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों की विधानसभा सीटों के लिए ग्राम प्रधान किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण कड़ी है। चुनाव जीतने, वोट प्रतिशत बढ़ाने, बूथ प्रबंधन करने, चुनाव प्रचार करने, रैलियों में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी उनके हाथ ही होती है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

यूपी में पंचायत चुनाव होने में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव कब तक करवाएंगे। संभावित तारीख बताइए। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ बुधवार को प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में ओमप्रकाश प्रजापति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख दी है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करिए। चुनाव आयोग से कहा कि वह उस दिन पंचायत चुनाव की संभावित तारीख लेकर आए। ओमप्रकाश के वकील अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना कि ओबीसी आयोग छह माह में रिपोर्ट देगा। दरअसल, पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण के निर्धारण के लिए सरकार ने समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, जो छह माह में अपनी रिपोर्ट देगा। इसकी रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की बात कही जा रही थी। लेकिन, अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करनी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी पंचायत चुनाव की तिथि कोर्ट को बतानी है। याची ओमप्रकाश प्रजापति ने कहा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3)(क) के अनुसार ग्राम प्रधान का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तिथि से अधिकतम पांच साल का होता है। लेकिन समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराकर मौजूदा प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया। यह उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने जैसा, जो कानून के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पहले जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते थे, तब ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए एडीओ पंचायत अथवा अन्य सक्षम अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाता था। इसलिए इस बार भी किसी सरकारी अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी।प्रदेश की 57 हजार 694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। इससे एक दिन पहले 25 मई को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पंचायत चुनाव संपन्न होने अथवा अगले छह माह तक मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल जनहित याचिका पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई तक था, जबकि लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 10 जून को होगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हो चुका है। आयोग बनने के 3 से 6 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा। इसके बाद चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण होगा। इसमें 6 महीने का समय लग सकता है। विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों की विधानसभा सीटों के लिए ग्राम प्रधान किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण कड़ी है। चुनाव जीतने, वोट प्रतिशत बढ़ाने, बूथ प्रबंधन करने, चुनाव प्रचार करने, रैलियों में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी उनके हाथ ही होती है। यदि किसी कर्मचारी को प्रशासक नियुक्ति किया जाता तो निवर्तमान ग्राम प्रधान उतने प्रभावी नहीं होते। वह सत्तारूढ़ दल के लिए उतने मददगार भी साबित नहीं होते।

KGMU में करोड़ों का दवा घोटाला यूएचआईडी नंबर चुराकर चलता था फर्जीवाड़ा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के यूरोलॉजी विभाग में गरीब और गंभीर मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए चल रही असाध्य रोग योजना में एक बड़े दवा घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में सामने आया है कि जालसाजों ने फर्जी मरीजों के नाम पर करोड़ों रुपये की महंगी दवाएं खरीदीं और उन्हें खुले बाजार में बेच दिया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद केजीएमयू प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जांच समिति की सिफारिश पर एक नियमित फार्मासिस्ट और तीन संविदा कर्मियों सहित कुल चार कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। असाध्य रोग योजना के तहत पहले हर महीने करीब 10 लाख रुपये की दवाओं की खरीद होती थी। लेकिन वर्ष 2026 की शुरुआत होते ही यह खर्च अचानक तीन से चार गुना बढ़ गया और बीते महीने यह आंकड़ा 45 लाख रुपये तक पहुंच गया। कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं की इस असामान्य खपत ने अधिकारियों को चौंका दिया। संदेह होने पर जब मरीजों के दस्तावेजों की स्क्रूटनी की गई, तो बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका सच साबित हुई। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीन पैरामेडिकल डॉ. केके सिंह की अगुवाई में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की, जिसने ढाई करोड़ रुपये के इस पूरे घालमेल को बेनकाब किया।

अपने दोस्त को साथ मिलकर बनाई हत्या की योजना सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

साउथ मलाका में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मंगलवार को कारोबारी, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे की लाश घर में पाई गई थी। सिर को कूंचकर उनकी हत्या की गई थी। हत्या को अंजाम रविवार को ही दिया गया था। जिस बेटे की लाश कारोबारी के साथ पाई गई थी, उसी ने दोस्त के साथ मिलकर माता-पिता और बहन की हत्या की थी। इसके बाद दोस्त के हाथों वह भी मारा गया। शहर के साउथ मलाका में हुए कारोबारी, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे के सामूहिक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या को अंजाम कारोबारी के बेटे ने ही दिया था, जो बाद में खुद भी बंटवारे के विवाद दोस्त के हाथों मारा गया। पुलिस के अनुसार कारोबारी के बेटे अभिषेक ने ही अपने एक दोस्त की मदद से अपने माता-पिता, बहन की हत्या कर दी। इसके बाद घर में रखे सारे जेवरात लूट लिए। बंटवारे को लेकर विवाद होने के बाद दोस्त ने अभिषेक को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने बुधवार को घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार रविवार को हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जबकि बदबू आने पर मंगलवार को घटना का पता चला था। इस मामले में चौकी इंचार्ज समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। vअभिषेक वैश्य ने अपने दोस्त शनि गुप्ता के साथ मिलकर अपने ही घर में लूटपाट और माता-पिता और बहन के सफाए की योजना बनाई। उसके बुलावे पर शनि गुप्ता रविवार की रात को लोहे की पाइप लेकर आ गया। पहले दोनों ने बैठकर बीयर पी। इसके बाद

दोनों ने मिलकर कारोबारी, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद पूरे घर में लूटपाट कर जेवरात और नकदी को एकत्र किया। मौके पर ही दोनों के बीच लूट के माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद शनि गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी। बहुत ही शातिर तरीके से उसने गत्ते पर लिख दिया, बंटी और बबली ने मारा है। ताकि हत्या का आरोप कारोबारी के छोटे बेटे और बहू पर लगे। छोटा बेटा फिलहाल जेल में बंद है।

नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत

ससुरालवालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ से बैंकॉक के बीच उड़ान भरने वाली थाई एयर एशिया की सीधी उड़ान पांच जून से बंद कर दी जाएगी। ईंधन संकट के चलते यह सेवा बंद की जा रही है। जबकि पिछले महीने मलयेशिया की सीधी उड़ान बंद कर दी गई है। ईरान व अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के चलते ईंधन संकट बरकरार है। इसका असर विमान सेवाओं पर भी पड़ रहा है। लखनऊ से मलयेशिया के क्वालालंपुर के बीच संचालित होने वाली एयर एशिया की सीधी उड़ान बंद कर दी गई है। वहीं, बैंकॉक जाने वाली थाई एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट पांच जून से बंद कर दी जाएगी। थाई एयर एशिया की बैंकॉक से लखनऊ आने वाली सीधी उड़ान संख्या एफडी-146 रात 8:25 बजे उड़ान भरकर रात 10:51 बजे पहुंचती है। वापसी में लखनऊ से बैंकॉक जाने वाली उड़ान संख्या एफडी-147 रात 11:05 बजे उड़ान भरकर सुबह 3:38 बजे पहुंचती है। ईंधन संकट के चलते विमान सेवा को पांच जून से बंद कर दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि लखनऊ से बैंकॉक की थाई एयर एशिया की सीधी उड़ान से सर्वाधिक हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी होती थी। दर्जनभर से अधिक मामले कस्टम की टीम ने पकड़े हैं। ऐसे में सीधी उड़ान बंद हो जाने से गांजे की तस्करी पर भी विराम लगने की संभावनाएं अफसर जता रहे हैं।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) अपनी परीक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए (एआई) का प्रयोग करेगा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) अपनी परीक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का प्रयोग करेगा। इसके तहत अब परीक्षा केंद्र पर टैबलेट से छात्र-छात्राओं की हाजिरी लगेगी। इससे गड़बड़ियों पर रोक तो लगेगी ही वहीं अगर कोई भी विद्यार्थी प्रवेश पत्र नहीं लेकर आया है तो भी वह परीक्षा से रोका नहीं जाएगा। पिछले दिनों नोएडा के एक केंद्र पर क्रिडेंशियल के दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद एकेटीयू ने परीक्षा में एआई के प्रयोग का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने अपने यहां सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज (कैस) में एमटेक द्वितीय सेमेस्टर में इसका प्रयोग शुरू किया है। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि इसके तहत परीक्षा कक्ष में प्रत्येक विद्यार्थी की हाजिरी टैबलेट के माध्यम से कराई जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत टैबलेट में विद्यार्थी के प्रवेश पत्र का पूरा डाटा पहले से अपलोड होता है, ऐसे में जैसे ही हाजिरी लगाई जाती है, डाटा मैच हो जाता है।

यूपी को मिला स्थायी पुलिस प्रमुख

उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से चली आ रही स्थायी पुलिस प्रमुख की कमी आखिरकार पूरी हो गई है। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण को पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। यह फैसला संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा भेजे गए पैनल में तीन नामों में से एक को चुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंजूरी देने के बाद लिया गया। गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के रहने वाले राजीव कृष्ण का जन्म 26 जून 1969 को हुआ था और वे 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। लगभग तीन दशक से अधिक के अपने करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है– पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG), महानिरीक्षक (IG), अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) और फिर 1 फरवरी, 2024 को पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद पर पदोन्नत हुए। वर्तमान में वे DGP मुख्यालय और सतर्कता विभाग लखनऊ का कार्यभार संभाल रहे थे। राजीव कृष्ण अपने शानदार सेवाकाल के लिए कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें पुलिस मेडल, मेधावी सेवा के लिए पुलिस मेडल, राष्ट्रपति पुलिस पदक और डीजीपी के कमेंडेशन रोल के साथ-साथ सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम कमेंडेशन डिस्क

से भी सम्मानित किया जा चुका है। गौरतलब है कि मई 2022 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई स्थायी डीजीपी नहीं था। राजीव कृष्ण 1 जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी चल रहे थे। अब जून 2029 में उनकी सेवानिवृत्ति तक उन्हें नियमानुसार कम से कम दो साल का स्थायी कार्यकाल मिलने की संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के डीजीपी का कार्यकाल दो साल का अनिवार्य होता है। इस रेस में 1990 बैच की रेणुका मिश्रा, 1991 बैच के आलोक शर्मा (वर्तमान में SPG डायरेक्टर) और पीयूष आनंद जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन UPSC के पैनल और सरकार ने राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर लगा दी। 26 मई, 2025 को UPSC, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) की बैठक में सीनियरिटी और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर तीन नामों का पैनल बनाया गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने अंतिम मंजूरी दी।

रिंग रोड निर्माण के लिए प्रशासन की कार्रवाई

बाधक निर्माण बुलडोजर से हटाए गए

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जनपद के कड़ेड पतारी गांव में प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना को गति देने के लिए बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य में बाधा बन रहे मकानों और अन्य अवरोधक ढांचों को बुलडोजर की मदद से हटवा दिया। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। पूरे अभियान की निगरानी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके।प्रशासन के अनुसार, रिंग रोड परियोजना जनपद की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं में शामिल है। इस परियोजना के तहत ऐसे सभी निर्माणों को हटाया जा रहा है जो प्रस्तावित मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कार्रवाई शुरू होने से पहले कई प्रभावित परिवारों ने अपने घरों से आवश्यक सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। वहीं कुछ परिवारों को अंतिम समय में अपने घरेलू सामान और अन्य वस्तुओं को निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।कार्रवाई के दौरान सदर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम सक्रिय रही। टीम में कानूनगो अरविंद श्रीवास्तव, लेखपाल सत्यम शुक्ला, मनीष शुक्ला और मनोज यादव सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और कहीं से किसी बड़े विरोध या तनाव की सूचना नहीं मिली।अधिकारियों ने बताया कि रिंग रोड का निर्माण पूरा होने के बाद शहर में यातायात व्यवस्था को काफी राहत मिलेगी। विशेष रूप से भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग

उपलब्ध होने से शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों का आवागमन अधिक सुगम हो सकेगा। इसके अलावा परियोजना से क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।कार्रवाई के दौरान कड़ेड पतारी गांव के ग्राम प्रधान मनोज भी मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। ग्राम प्रधान ने कहा कि रिंग रोड बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे स्थानीय व्यापार, परिवहन और अन्य सुविधाओं को लाभ मिलेगा।प्रशासन ने दावा किया कि सभी प्रभावित लोगों को पूर्व में नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना से जुड़े सभी कार्य निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि रिंग रोड का निर्माण समय पर पूरा किया जा सके।

डिवाइडर से टकराकर पलटी कार

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

धार्मिक यात्रा पर निकले जयपुर का एक परिवार प्रयागराज से लौटते समय रविवार देर रात एक बजे उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गया। कार में सीएनजी खत्म होने का अलर्ट मिलने पर चालक गूगल मैप पर सीएनजी पंप की लोकेशन देखकर उस दिशा में बढ़ रहा था। एक कट पर कार नीचे की ओर उतारी तो रास्ता बंद होने से डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार चारों लोगों को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी के शीशे टूट गए। रवि कुमार शर्मा, अरविंद शर्मा, हर्ष शर्मा व कार्तिक कार से वाराणसी व प्रयागराज समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गए थे। प्रयागराज से गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते लौट रहे थे। कार रवि कुमार शर्मा चला रहे थे। उन्नाव में बेहटामुजावर में इंटरचेंज से उतर कर वह आगरा एक्सप्रेसवे से जयपुर जाने के लिए निकले। इस दौरान कार में ईंधन कम हो गया। गूगल मैप पर जोगीकोट गांव के पास हवाई पट्टी के निकट उन्हें सीएनजी पंप का रास्ता दिख रहा था। हवाई पट्टी स्थित इमरजेंसी कट से कार नीचे मोड़ी तो आगे रास्ता बंद होने से ब्रेक लगाई। कार अनियंत्रित होकर पलट गई। यूपीडा की टीम ने सभी को कार से बाहर निकाला। बताया कि बांगरमऊ क्षेत्र में कोई भी सीएनजी पंप नहीं है। अनुमान है कि हरदोई के मल्लावां क्षेत्र स्थित पंप का रास्ता मैप में देख कार सवार इमरजेंसी कट से नीचे उतरने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गए।

सरैयां रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के तहत गर्डर स्थापित करने का कार्य

उन्नाव के सरैयां रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के तहत गर्डर स्थापित करने का कार्य बुधवार को शुरू हो गया। यह कार्य मंगलवार से प्रारंभ होना था, लेकिन तैयारियों में कमी के कारण इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। कार्य शुरू होने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, जिससे वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। लखनऊ से आए रेलवे के एक्सईएन अनिल तिवारी ने पहले मंगलवार को ही गर्डर रखने का काम शुरू करने का दावा किया था। इसके लिए सरैयां मार्ग को बंद कर रूट डायवर्जन लागू करने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि, मौके पर आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं की कमी के कारण देर रात योजना में बदलाव करना पड़ा और कार्य को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार सुबह रेलवे प्रशासन से आवश्यक ब्लॉक मिलने के बाद भारी मशीनरी की सहायता से गर्डर स्थापित करने का काम शुरू किया गया। इस कार्य के लिए तीन विशाल क्रेनें तैनात की गई हैं, जिनमें एक 350 टन क्षमता की और दो 300 टन क्षमता की क्रेनें शामिल हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक अतिरिक्त क्रेन को रिजर्व में रखा गया है। गर्डर स्थापना के लिए अन्य आधुनिक मशीनें भी कार्यस्थल पर पहुंच चुकी हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह कार्य 3 जून से 7 जून तक लगातार चलेगा। कार्य की निगरानी के लिए डिप्टी चीफ इंजीनियर आशीष कुमार वर्मा और साइट इंजीनियर रोहित खन्ना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे क्रॉसिंग के आसपास स्थित दुकानों, मकानों और आबादी वाले क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि गर्डर स्थापित करते समय सुरक्षा के सभी मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट उन्नाव समेत सभी जिलों में कड़ी निगरानी के निर्देश

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मुख्य सचिव एस.पी. गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भर्ती परीक्षा 8 से 10 जून के बीच आयोजित होगी, जिसमें प्रदेशभर से लगभग 28 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 32,679 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली इस परीक्षा को लेकर उन्नाव सहित सभी जिलों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उन्नाव जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना बनाई गई है ताकि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। परीक्षा केंद्रों के आसपास सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारियों को परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने तथा परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के लिए यह भर्ती अभियान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।

राष्ट्रभक्ति और अनुशासन का संदेश देते निकले स्वयंसेवक

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

आरएसएस अवध प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण पूरन नगर स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को स्वयंसेवकों ने कब्बाखेड़ा स्थित आंबेडकर तिराहे से गणवेश में पथ संचलन शुरू किया। प्रशिक्षण में शामिल होने विभिन्न जिलों से पहुंचे स्वयंसेवक शिक्षार्थी पथ संचलन में शामिल हुए। हाथों में दंड व दिलों में राष्ट्र भक्ति का भाव संजोये शिक्षार्थियों ने सैनिकों की भांति कदम से कदम मिलाते हुए पथ संचलन करते हुए सामूहिक एकता व अनुशासन का परिचय दिया। सिविल लाइन में तिराहे पर पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भाजपाइयों ने स्वयंसेवकों का अभिवादन भी किया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य आनंद अवस्थी, सदर विधायक पंकज गुप्ता, विधायक श्रीकांत कटियार, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, नवीन सिंह, अनिल कुशवाहा, नूतन सिंह, रजनीश वर्मा, विमल द्विवेदी, संजीव त्रिवेदी, मीडिया प्रभारी विजय द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों में फंसीं 4.38 अरब की सीवरेज परियोजनाएं

शहर को जलभराव से निजात और गंगा नदी को निर्मल बनाने की 4.38 अरब की दो योजनाएं पाइप लाइन में रेत भरने चोक हो गई हैं।इस कारण वर्ष 2019 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमजीसी) के तहत 3.80 अरब की एसटीपी और शहर के सीवरेज और नालों के पानी को पंप स्टेशनों के लिए एसटीपी तक पहुंचाने की 58 करोड़ की परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाईं। इससे रोज 15 लाख लीटर गंदा पानी बिना साफ हुए गंगा में जा रहा है।शहर की जलनिकासी की समस्या को हल करने के साथ ही सीवरेज और गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत वर्ष 2019 में उन्नाव (शहर) और गंगाघाट (शुक्लागंज) नगर पालिका क्षेत्र के लिए 3.80 अरब की परियोजना मंजूर की थी। परियोजना के तहत लोनी और सिटी ड्रेन में गिरने वाले नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए गए हैं। शुक्लागंज में गंगा में गिरने वाले सात में से पांच नालों को पक्का करके इसी से जोड़ा गया है लेकिन अचलगंज के डकारी गांव में नदी के किनारे बनाया गया 15 एमएलडी (15 लाख लीटर पानी प्रति दिन) पानी साफ करने की क्षमता वाला एसटीपी दो साल से काम नहीं कर पा रहा है। भूमिगत पाइप लाइन में रेत भरने से पाइप लाइन चोक हो गई है। डकारी एसटीपी चालू न होने से अमृत योजना की 58 करोड़ से शहर के पीतांबर नगर, शिव नगर सहित अन्य मोहल्लों क्षेत्रों में भूमिगत सीवरेज पाइप लाइन और शिव नगर में इंटरमीडिएशन स्टेशन (आईपीएस) आदर्शनगर में 30 एमएलडी क्षमता का मेन पंपिंग स्टेशन (एमपीएस) भी काम नहीं कर पा रहा है। शिवनगर के आईपीएस को आदर्शनगर के एमपीएस से जोड़ने के लिए पांच किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइप लाइन डाली गई है। इसके बाद 10 किलोमीटर भूमिगत पाइप लाइन डालकर शहर के एमपीएस को डकारी के एसटीपी से जोड़ा गया है लेकिन बनने के बाद भी यह काम नहीं आ रहे हैं। शहर का गंदा पानी लोनी ड्रेन में गिरता है। इसी ड्रेन में दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र और शहर के सीवर पंप हाउस का भी पानी जाता है। करीब 150 किलोमीटर लंबी यह ड्रेन शहर के दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र से बीघापुर तहसील से बिहार कस्बा होते हुए रायबरेली जिले के लालगंज क्षेत्र में भोजपुर गांव के पास गंगा नदी में मिलती है।

कार्यकाल खत्म, फिर भी प्रधान प्रशासक:
यूपी सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें ही संबंधित पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया है।सरकार के इस फैसले को कानून की मंशा के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका दाखिल की गई है।मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी, जबकि पंचायत चुनाव और नई जनगणना को लेकर भी बहस तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश सरकार के उस फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें ही संबंधित पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के अनुरोध पर अगली सुनवाई के लिए 3 जून की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की। यह याचिका ओमप्रकाश प्रजापति की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतोंके प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर संबंधित ग्राम प्रधानों को ही उनकी पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी फिलहाल उन्हीं प्रधानों के पास बनी हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करना कानून की मूल भावना और मंशा के विपरीत है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार के इस आदेश को निरस्त किया जाए और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था लागू की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अब इस महत्वपूर्ण मामले पर 3 जून को विस्तृत सुनवाई होगी, जहां राज्य सरकार और याचिकाकर्ता दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखेंगे। बता दें कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के मुताबिक, पिछड़ा आयोग अभी 2011 की जनगणना के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जबकि पिछले 15 वर्षों में सामाजिक और जनसंख्या संबंधी हालात काफी बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा है कि पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। संगठन सरकार और आयोग के सामने नई जनगणना के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की मांग रखेगा।

प्रदेश में खुलेंगी 489 नई शराब दुकानें, राजस्व बढ़ाने की तैयारी में सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य के 43 जिलों में 489 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। आबकारी विभाग के अनुसार, नई दुकानों के संचालन से सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि हुई है और शराब की मांग अधिक है, वहां नई दुकानों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई दुकानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।सरकार का तर्क है कि आबकारी राजस्व राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस वर्ष सरकार ने आबकारी विभाग को बड़ा राजस्व लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई।हालांकि इस निर्णय पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ सामाजिक संगठनों ने शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार को नशामुक्ति अभियानों को भी समान प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि सभी दुकानें निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार संचालित होंगी।विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से राज्य की आय बढ़ सकती है, लेकिन इसके सामाजिक प्रभावों पर भी लगातार नजर रखने की आवश्यकता होगी।

कुशीनगर का फाजिलनगर अब कहलाएगा पावागढ़, मुख्यमंत्री योगी ने किया बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के ऐतिहासिक कस्बे फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय भगवान महावीर की स्मृतियों और क्षेत्र की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पावागढ़ जैन धर्म और भगवान महावीर के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। सरकार का मानना है कि नाम परिवर्तन से क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।राज्य सरकार के अनुसार, नाम परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां मिलने के बाद इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को भी संबंधित तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।राजनीतिक दृष्टि से भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को उनकी मूल पहचान दिलाने का कार्य कर रही है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को विकास और रोजगार जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो पावागढ़ धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की संभावना है।

विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने तेज की संगठनात्मक तैयारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) ने राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने और नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने के लिए दो-स्तरीय रणनीति पर काम शुरू किया है।सूत्रों के अनुसार पार्टी संगठन के पुनर्गठन के साथ-साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना बना रही है। आरएलडी नेतृत्व का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का पारंपरिक आधार अभी भी मजबूत है और उसे और विस्तार देने की आवश्यकता है।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन प्रमुख दलों ने अपनी रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी सभी संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियानों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।इन तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक सक्रिय होने वाली है तथा विभिन्न दल जनता के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास करेंगे।ये चारों समाचार अखबार के उत्तर प्रदेश पृष्ठ के लिए पहले वाले समाचारों की तुलना में अधिक संतुलित और समाचार-मूल्य वाले हैं।